राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया जाना

4436. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुजरात सहित राज्यों में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किये गये थे।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंको के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन जीन बैंकों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन बैंकों के कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। लेकिन मध्यम अवधि के बीज भण्डारण मोडूल्स गुजरात सहित अनेक राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों को दिए गए हैं।

(ख) जीन बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य आनुवंशिक विविधता का संरक्षण और इसे फसल सुधार के लिए उपलब्ध कराना है।

साझा इंडो-यू० एस० ए० आई० डी० पी० जी० आर० प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन मुख्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। जीन बैंक में 12 दीर्घकालिन भण्डारण मोडूल्स (—20०सै०) और मध्यम अवधि तक भण्डारण का मोडूल (+ 4०सै०) है। इसके अलावा II मध्यम अवधि के भण्डारण मोडूल्स विभिन्न संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालयों को भा० कु० अ० प० पद्धति के तहत दिए गए हैं। ये संस्थान गुजरात, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (3), महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं। इसमें एक कोया बैंक (तरल और नाइट्रोजन में ०196०सै० पर भंडारण) और टिशू कल्चर भंडारण (10०सै० से 25०सै०) भी है।

(ग) अब तक एन० बी० पी० जी० आर० काम्पलैक्स के निर्माण पर 17.84 करोड़ रु० का व्यय हुआ है। (50% का भुगतान यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा किया गया)। जीन बैंक के लिए प्रयोगशाला के औजार और दूसरे उपस्कर खरीदने के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर खर्च हुए हैं। यू० एस० ए० आई० डी० के योगदान से 4.5 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा और 0.5 मिलियन की स्थानीय मुद्रा प्राप्त हुई है। पूरी प्रयोजना को 27.95 मिलियन अमेरिकी डालर के कुल व्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) जर्मप्लाज्म भण्डारण और संरक्षण वर्ष 1997 की दूसरी तिमाही में कार्य करना शुरू करेगा और 13 मोडूल्स को नियोजित तरीके से भरा जाएगा। इस समय जीन बैंक की उसके कारगर ढंग से कार्य करने के लिए जांच की जा रही है।

गुजरात में तिलहनों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विस्तार

4437. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में तिलहनों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किये गये लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य में खाद्य तेलों की गुणवत्ता में वृद्धि करने और उसे बुनियादी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी हां। तिलहनों के उत्पादन संबंधी नीति में क्रमिक फसलन, अन्तः-फसलन, आर्थिक दृष्टि से कम लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर दूसरी फसलें लगाने और विभिन्न तिलहन फसलों के अन्तर्गत समस्या वाले क्षेत्रों/परिस्थितियों में प्रतिस्थापन फसलों के माध्यम से क्षेत्र में विस्तार के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। उच्चतर क्षेत्र की कवरेज को प्रोत्साहित करने के लिए, गुजरात राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) क्षेत्र की दृष्टि से लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाता। तथापि, आठवीं पंच वर्षीय योजना के

दौरान राज्य में तिलहनों का उत्पादन और उपलब्धियां नीचे प्रदर्शित किए गए हैं:

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	उत्पादन उपलब्धि
1992-93	25.00	31.86
1993-94	31.50	15.72
1994-95	30.00	37.07
1995-96	29.00	21.64
1996-97	28.50	35.94 (प्रत्याशित)

(घ) जी हां। 1996-97 के दौरान केन्द्रीय प्रयोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत तिलहनों तथा खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मूलतः 500.00 लाख रुपए के बजट आवंटन की तुलना में गुजरात राज्य को 690.00 लाख रुपए का संशोधित बजट आवंटन किया गया है।

State of Floriculture in the Country

4438. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been drawn to a recent study conducted by the Export-Import Bank of India to the present state of floriculture and its export potential; and

(b) if so, the steps being contemplated by Government to remove the major impediments listed in the report to boost floriculture in the country?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) (i) Ministry of Agriculture implemented a Central Sector Scheme on Commercial Floriculture with an outlay of Rs. 14.29 crores in all the States/UTs of the country during the 8th Plan. Major amphasis was on providing quality planting material; training on production and post-harvest management; and on areas expansion. The Scheme is likely to be continued during the Ninth Plan period.

(ii) National Horticulture Board under Ministry of Agriculture, provides a soft loan of upto Rs. one crore to integrated projects on production and post harvest management including marketing with focus on exports. During the Eighth Plan period Rs. 52.68 crores were sanctioned for assisting 61 projects on floriculture located in the States of Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

(iii) APEDA (Ministry of Commerce) is assisting in setting up facilities for separate handling of export Cargo of perishable items at Mumbai and Delhi Airports.

(iv) Wholesale market-cum-auction Centres are planned to be set up by APEDA at 5 major cities viz. Delhi, Mumbai, Pune, Chennai and Bangalore.

(v) APEDA is implementing a UNDP assisted project on floriculture aimed at achieving an expansion of the cut flower export sector based on improved production expertise and market knowledge.

(vi) The Government of India has simplified and streamlined the procedures of plant material imports, particularly for export oriented projects.

(vii) Import duty on several important equipments etc. required in 100% Export Oriented Units has been waived/reduced.

(viii) APEDA is implementing schemes for development of infrastructures, packaging, marketing (including air freight subsidy) to facilitate exports of floriculture products from the country.